MR. SPEAKER: Now, we come to amendments. Mr. Yadav, are you pressing your amendment?

श्री कुम्भ देव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

(The Amendment No. 1 was by leave, withdrawn.

श्री राम किशन : अध्यक्ष महोदय, मै सदन से अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हू ।

The Amendments No. 3 was by leave withdrawn)

MR. SPEAKER: Mr. Yuvraj, are you pressing your amendment?

SHRI YUVRAJ: Yes.

MR. SPEAKER: The question is:

'That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 9th May, 1978."

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: Now, we come to the Bill. The question is:

"That the Bill to provide interest for the demonetisation of certain high denomination bank notes and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: There are no amendments. The question is:

"That clause 2 to 15 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 15 were added to the Bill

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Schedule was added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI H. M PATEL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

'That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Sir, I have a request to make to the House. There are two more Bills to be passed. The Rajya Sabha is adjourning tomorrow. I would request the hon. Members to agree that the sitting of the House may be extended today to pass the remaining two Bills according to the list of Business.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): What is the hurry about it? You send it to the Joint Committee. We have to go deep into it.

SHRI BIJU PATNAIK: I am only requesting you to extend the time of the House.

17.37 hrs.

HINDUSTAN TRACTORS LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL.

MR. SPEAKER: We now take up the next item; Shri George Fernandes.

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव* करता हूं :

"कि जन साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, विश्वामित्री, बड़ोदरा के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक पर विवाद की कोई गुंजाइश हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): Sir, on a point of information.

The matter in *sub judice*, it is already in the court and applications have been made......

MR. SPEAKER: In legislative measures, there is no question of *sub judice* at all. The Parliament is supreme.

श्री जार्ज फर्नान्डिस : मैं जैसा कह रहा था, यह ऐसा विधेयक है जिस पर कोई खास विवाद की गुंजायश नहीं है। 1973 के मार्च में आई० डी० आर० ऐक्ट के अन्तर्गत, हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स जो बड़ौदा में कारखाना है, ट्रैक्टर बनाने वाला, उसको सरकार ने अपने हाथ में लिया था और गुजरात एग्रो एण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, जो सरकारी क्षेत्र में बनी हुई संस्था है उस संस्था के हाथों में इसको चलाने की जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद अब पांच साल पूरे हो रहे हैं। इन पांच सालों मे गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन ने इस कारखाने को चलाते हुए इसकी स्थिति में काफी सुधार करने में कामयाबी पाई है। जिस साल इसको सरकार ने अपने ताबे में लिया उस साल इस कारखाने में कुल 80 लाख रुपया का घाटा था। पिछले साल उस घाटे को लगभग 8 लाख पर लाने में गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को कामयाबी मिली। और इस साल पहली बार कई वर्षों के बाद यह कारखाना मुनाफा दिखायेगा, ऐसा अंदाज है। मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन लगभग एक लाख रुपए का मुनाफा इस साल पहली बार इस कारखाने को होगा।

बीमार अवस्था में इस कारखाने को सरकार ने लिया था, जिस तरह से दूसरे बीमार उद्योगों को सरकार को लेना पड़ता है। इस कारखाने को लेने से पहले इस की जांच हुई थी, जिस तरह से दूसरे कारखानों की जांच होती है और उस जांच मे एक बात यह भी दिखाई दी कि इस कारखाने को जिस तरह से चलाया जा रहा था, वह ठीक नहीं था। इस तरह की स्थिति इस देश में हर रोज दिखाई देती है कि कारखाने को चलाने का ढंग ठीक न होने के कारण उसमें बीमारी आ जाती है और इसमे सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है, तो वह मजदूरों के साथ होती है। मगर कभी-कभी हमारे सामने ऐसी समस्या भी खड़ी हो जाती है कि अगर किसी बीमार उद्योग को ले लिया जाय और उसके बाद सब लोगों की मेहनत के चलते, जिसमे मजदूरों का सबसे ज्यादा योगदान होता है, उस कारखाने को सुधारने का काम सफल हो जाये, तो पांच साल के पूरे होते ही जो पुराने मालिक होते है, वे फिर आगे आ जाते है और कहने लगते है कि अब कारखाना ठीक से चलने लगा है, हम भी अब इसको ठीक से चला सकते हैं, लेकिन इस मामले में अनुभव कुछ और ही होता है। जो सदन में उस तरफ़ बैठने वाले लोग है, वे भी ऐसा कर चुके हैं और हम भी कर रहे है। इसलिये जब मै इस विधेयक

*Moved with the recommendation of the President.

को सदन के सामने ला रहा हूं—तब मैं इस चीज को महसूस करता हूं—काफ़ी लोगो का भी इस बात का आग्रह रहा—कि यह कारखाना चूंकि अब नई स्थिति मे पहुंच रहा है और अगले पांच वर्षों मे हम इस का जो भविष्य देख रहे है—वह भी काफ़ी प्रगति करने वाला दिखाई दे रहा है, जैसे पाच साल के पहले इस कारखाने का कुल टर्न-ओवर 2 करोड रुपये सालाना था, जो अब 8 करोड रुपये से ज्यादा है और अगले पाच सालो का जो हमने प्रोजैक्शन किया है, उसके चलते पांच वर्ष के बाद इसका टर्न-ओवर लगभग 23 करोड रुपये तक आ जायगा—इन सारी बातो को दृष्टि मे रखते हुए सरकार इस नतीजे पर पहुची कि इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय मैंने पहले कहा है कि इस पर कोई वाद-विवाद की गुजाइश नही है। ऐसा कहने के पीछे एक खास कारण भी है—इसके राष्ट्रीयकरण का पहला प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अक्तूबर, 1976 मे आया था। उस समय गुजरात मे राष्ट्रपति शासन था और केन्द्र मे कांग्रेस सरकार थी, यानी वहां सरकार थी जो वहा राष्ट्रपति शासन का चला रही थी। तो उस समय राज्य की तरफ से केन्द्र के पास यह प्रस्ताव आया कि कारखाने का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, क्योंकि दूसरा कोई तरीका इस कारखाने को चलाने का नही है। उस प्रस्ताव के आने के कुछ महीने के बाद गुजरात मे कांग्रेस दल की सरकार बन गई और केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने, चूंकि पहले जो प्रस्ताव आया था, वह राष्ट्रपति शासन के चलते आया था, वहा के गवर्नर, उनके एडवाइजर और वहा का जो उद्योग विभाग है, उसकी तरफ से आया था, यह तय किया कि अब चूंकि वहा नई सरकार बन गई है, इस लिये हम उनकी राय का जानना चाहेंगे, यह कह कर उस प्रस्ताव का फरवरी, 1977 मे गुजरात राज्य का वापस भेज दिया। वहा इस पर पुनर्विचार हुआ और उस पुनर्विचार के बाद जो प्रस्ताव हमारे पास आया...

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) Was it returned by the Government?

SHRI GEORGE FERNANDES: The first proposal came in October 1976 from the Gujarat Government suggesting nationalization of this unit At that time, Gujarat was under President's rule. In February 1977, that is before the last general elections, when the Congress Ministry was formed in Gujarat; Bahubhai Patel went out in March, 1976; in October, 1976 there was President's rule, a month or two thereafter, a popular Ministry was installed there.

SHRI VAYALAR RAVI: Shri Madhavsinh Solanki was the Chief Minister

SHRI GEORGE FERNANDES: Yes, the Central Government at that point of time referred the matter back to the State Government with a suggestion that since this proposal came at the time of the President's rule, we would now like to have the opinion of the new Government. Further changes came about thereafter in the Government and we had the Gujarat Government later on interact with the Central Government and tell us again that the Gujarat Government stood by its earlier proposal to nationalise this unit

मगर केन्द्र और गुजरात राज्य दोनो मे जो बातचीत हो गई, उसके सन्दर्भ मे और विशेष कर स्टेट बैंक आफ इण्डिया से, जिसके दस

[श्री जार्ज फर्नान्डिस]

कारखाने मे कई करोड़ रुपये लग गये है—ढाई करोड रुपये स्टेट बैंक आफ इण्डिया के इस कारखाने मे फसे हुए हैं—इस मसले पर काफी चर्चा हुई है और उस चर्चा के चलते एक नई जाच इस कारखाने के बारे मे फिर से करने मे आ गई और उस जाच के होने के बाद यह प्रस्ताव बहुत स्पष्ट तौर पर गुजरात सरकार मे आ गया और गुजरात सरकार इस बात पर बिल्कुल हो गई कि इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हमने गुजरात सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि हम यह मानते है कि कारखाने का राष्ट्रीयकरण करने से इस कारखाने मे बनने वाली चीजो का, इस कारखाने मे काम करने वाले मजदूरो का भला हो सकता है।

एक आखरी बात मे इस मामले पर और कहा जायगा और वह यह है कि जब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र वगैरह पर बहस होती है, तो कौन कारखाना किस मैनेजमेंट के हाथ मे चलती है तब अधिकांशत हम इस बात को भूल जाते है कि उसमे ज्यादा पूजी किस की लगी हुई है और यह मानते है कि जिस किसी एक परिवार के हाथ मे या जिस किसी गिरोह या समूह के हाथ मे वह उद्योग होता है, सारी पूजी उस परिवार या उस समूह की ही उस कारखाने मे पडी हुई है। यह बहुत बडी गलतफहमी है जैसे यह कारखाना एक परिवार के नाम मे है और इस कारखाने मे वह परिवार पहले जुडा हुआ था मगर जो इतनी सारी पूजी इस कारखाने मे लगी है, उसमे से केवल 17 प्रतिशत ही उस परिवार की पूजी है और 83 प्रतिशत पूजी सार्वजनिक सस्थाओ की जैसे एल० आई० सी० यू० टी० आई०, ओरियेन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेंस और दूसरी पब्लिक सेक्टर अन्डर-टेकिंग्स की है। कुल मिला कर 83 प्रतिशत पूजी उनकी इसमे पडी है। इसलिए जब भी किसी एक सस्था को लिया जाता है और किसी कारणवश उसको लिया जाता है, तब यह चर्चा होती है जैसे हम किसी व्यक्ति या परिवार या किसी समूह पर हमला बोलने जा रहे है। इसमे कोई खास तथ्य नही है और इस कारखाने के सन्दर्भ मे मै यह बात इसलिए दोहरा रहा हू क्योकि काफी चर्चा, काफी बहस सार्वजनिक तौर पर और अन्य स्तरो पर इस बात पर हुई थी। इसलिए मैने इस बात को साफ करना जरूरी समझा। मुझे इस बारे मे और अधिक कुछ कहने की जरूरत महसूस नही हो रही है और मेरी प्रार्थना है कि यह सदन इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार करे।

MR SPEAKER Motion moved

'That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the undertakings of Hindustan Tractors Limited Vishwamitri, Vadodara, for the purpose of ensuring the continuity of production of goods which are vital to meet the needs of the general public and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration'

There are some notices of amendments Those members who want to move them may please do so now

SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV (Madhubani) I beg to move

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th June, 1978" (1)

DR VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh) I beg to move

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th July, 1978" (3)

SHRI VINAY PRASAD YADAV (Saharsa) I beg to move,

'That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1978" (5)

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से बराबर राष्ट्रीयकरण के बिलों का समर्थन किया गया है। फर्नांनडिस साहब इससे पहले भी जो बिल राष्ट्रीयकरण के बारे में लाये थे, हमने उनका भी समर्थन किया था। इस बिल के बारे मे मैं ज्यादा बहस में नहीं पड़ूगा क्योंकि वक्त कम है।

हमारे जितने बीमार कारखाने हैं उनको कैसे हाथ में लिया जाए, इसके बारे मे काफी आलोचना हुई है। मैं इस सम्बन्ध मे दो-एक आशंकाएं फर्नांनडीस साहब के सामने रखना चाहता हूं। मेरी पहली आशंका तो यह है कि जब कोई कारखाना केन्द्रीय सरकार अपने हाथ मे लेती है, या उसका राष्ट्रीयकरण करती है तो उसे केन्द्रीय सरकार अपने आप ही उस कारखाने को चलाती है, अपने ही डायरेक्टर्स नियुक्त करती है। इसलिए मेरे मन मे इसके परिचालन के बारे मे शंका है। जब इस कारखाने का परिचालन राज्य सरकार पर छोड़ा जा रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई सियासत है, यह मुझे आशंका है। क्योंकि गुजरात में बाबू भाई की मिनिस्ट्री है और वह मिनिस्ट्री फर्नांनडिस साहब की अपनी पार्टी की मिनिस्ट्री है। इसलिए यह शंका मेरे मन में है। (व्यवधान) क्या वहां बाबूभाई की मिनिस्ट्री नही है? क्या यह कारखाना उसके हाथ मे नही जा रहा है? क्या यह सच नही है?

दूसरे फर्नांनडिस साहब को मेरा कहना यह है कि इसके पहले भी उन्होंने कारखाने अपने हाथ मे लिये है। उन बीमार कारखानों के जो छोटे छोटे क्रेडिटर्स होते है उनको पैसा मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। बड़े मालिक तो अपना कम्पेन्सेशन ले जाते है लेकिन छोटे लोगों को पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। वेस्ट बंगाल में बहुत से बीमार कारखाने थे और उन्हे कुछ लोग माल सप्लाई किया करते थे। उनके सामने यह समस्या आ रही है। इसलिए मै मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में ध्यान दें। यह बात मैं इस कारखाने के बारे में नही कह रहा हूं। यह सुझाव मैं जनता पार्टी का जो इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन है, उस के सम्बन्ध मे दे रहा हू। आपने इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण किया इसके लिए तो मैं आपको बधाई दूगा लेकिन बीमार कारखानो के सम्बन्ध में आप जो इंडस्ट्रियल पालिसी अख्तियार करें, उसमे इस बात का ध्यान रखे।

आपकी जो इंडस्ट्रियल पालिसी है, उसमे लिखा है—

> "While Government cannot ignore the necessity of protecting the existing employment but the cost of maintaining such employment will also be taken into account."

फर्नांनडिस साहब इस स्टेटमेंट मे किन्तु आ गया है। आप जब बम्बई में थे तो कहते थे कि इस कारखाने को लेना है, उस कारखाने को लेना है। लेकिन अब इस स्टेटमेंट में किन्तु आ गया है। जब कांग्रेस सरकार थी, तब हमने देखा था कि बाहर से इतना प्रेशर रहता था कि इतना पैसा खर्च करके क्यों बीमार कारखाना लिया जा रहा है। इसलिए फर्नांनडिस साहब को ये सारी बातें जाननी होंगी और सोचना होगा कि जो बीमार कारखाने आप ले रहे है वे किस कंसीडरेशन से ले रहे हैं। पोलिटिकल कंसीडरेशन से ले रहे हैं। या इकोनोमिक कंसीडरेशन से ले रहे हैं। जो कारखाने आप ले रहे हैं उनमें कितने लोगो को नौकरी मिलेगी। ये सब बात सोचने की है।

ये मेरे तीन सुझाव है। मैं फर्नांनडिस साहब को इस बिल को लाने के लिए बधाई देता हू और इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करता हू।